फरीदाबाद
मजदूर समाचार

मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 146 अगस्त 2000

निराशा हैं आशा की किरण (2)

टैक्स, ब्याज, कट-कमीशन, डिविडेन्ड की अदायगी में कमी पड़ने पर कम्पनी को बीमार कहा जाता है। स्वस्थ करने का नुस्खा है: कम्पनी में कार्यरत मजदूरों के वेतन-भत्तों में कटौती, छँटनी द्वारा मजदूरों की सँख्या कम करना और बचे हुये मजदूरों के वर्क लोड में भारी वृद्धि। कम्पनी की तन्दरुस्ती बढाने – कम्पनी को बीमार होने से बचाने – बीमार कम्पनी को स्वस्थ करने के लिये साहब लोग बहुत पापड़ बेलते हैं। तेज-तर्रार और अनुशासन के साँचों में शिशुपन से ढले लोग कम्पनियों का संचालन करते हैं लेकिन फिर भी बड़ी सँख्या में कम्पनियाँ बन्द होती हैं। कौशल-तिकड़मबाजी की कमी कम्पनियों के बन्द होने का कारण नहीं है। बल्कि, कम्पनियों का बन्द होना मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन वाली वर्तमान व्यवस्था के संकट का एक लक्षण मात्र है। जरूरत तो मजदूरी-प्रथा के विकल्प की है। खैर।

बीमार कम्पनी को स्वस्थ करने की सम्भावना नहीं रहती तब कम्पनी बन्द होने से पहले की लूट चलती है। मुर्गी अण्डे देना बन्द कर देती है तब उसकी एक टाँग, फिर एक पँख, फिर ... नौची जाती हैं। हाँ, कम्पनी के क्लोजर-बन्द होने की बात को बहुत गुप्त रखा जाता है। छिपाने में मैनेजमेन्ट के संग उसका लीडरी विभाग अत्यन्त सक्रिय रहता है। अदलते-बदलते नेताओं का मजदूरों को बींधने का रामबाण है: हाथ बचाना है तो उँगली कटवाओ। कदम-कदम पर अपमानित-जलील कर मजदूरों की बोटी-बोटी नौची जाती है। हलाल होने की पीड़ा को "किसी तरह नौकरी बची रहे" के गरल-जहर के जरिये बरदाश्त करने को समझदारी पेश किया जाता है। "कम्पनी चलती रहेगी तो कुछ तो मिलेगा" का काँटा धँसता जाता है।

गेडोर हैन्ड टूल्स-झालानी टूल्स लिमिटेड के इन बीस वर्षों की कुछ घटनाओं पर विचार-विमर्श हकीकत की कई परतें खोलने के लिये एक उपयुक्त उदाहरण है।

लाइलाज बीमारी

– मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन वाली वर्तमान व्यवस्था के संकट को 1980 में साहब लोगों ने विश्व मन्दी कहा। इसकी चपेट में सोने के अण्डे दे रही गेडोर हैण्ड टूल्स भी आई। कम्पनी को स्वस्थ रखने के लिये छँटनी, वेतन कटौती और आटोमेशन के जरिये वर्क लोड वृद्धि का 1982 में ऐलान हुआ।

– मजदूरों ने अपनी बलि देने से इनकार कर दिया। नेता बदले पर वही ढ़ाक के तीन पात। मैनेजमेन्ट ने पुलिस-प्रशासन की छत्रछाया में लीडरों की कमेटी के जरिये फैक्ट्री के अन्दर मजदूरों की पिटाई का सिलसिला चला कर 1984-85 में 1500 मजदूरों से जबरन इस्तीफे लिखवाये।

– छँटनी और आटोमैटिक प्लेटिंग प्लान्ट लगाने के बावजूद कम्पनी के स्वस्थ होने के कोई लक्षण नजर नहीं आये तो गेडोर (जर्मनी) ने अपना हिसाब कर लिया। कम्पनी का नाम बदल कर झालानी टूल्स लिमिटेड।

अण्डे नहीं तो टाँग खाओ

– कम्पनी बीमार घोषित और 1987 से ही बी.आई.एफ.आर. की छत्रछाया में। कम्पनी को स्वस्थ करने के नाम पर 1988 में स्कीम पास जिसमें मजदूरों के 8 घण्टे के उत्पादन को 4 घण्टे का उत्पादन करार दिया गया।

– कम्पनी ने गेडोर से हिसाब-किताब के समय वरकरों के लिए 105 दिन की सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसों का प्रावधान किया था। स्वास्थ्यलाभ की आड़ में मैनेजमेन्ट ने उन सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसों को ठिकाने लगा दिया। आगे की ग्रेच्युटी के लिये प्रावधान किया ही नहीं और कम्पनी की सम्पत्ति ऊपर से बेची। मजदूरों को बहकाने के लिये मैनेजमेन्ट ने 1988-92 के दौरान 8 महीनों की बकाया तनखा 200 रुपये की किस्तों में दी। पाँच हजार दे कर मजदूरों के 95 हजार डकारने का नतीजा है रिटायर मजदूरों को सर्विस-ग्रेच्युटी के भी पैसे नहीं दिये जाना।

ग्रीस की, रिश्वत की महिमा

– कम्पनी ने बैंकों को ब्याज भी नहीं दिया इसलिये बी.आई.एफ.आर. ने कम्पनी को स्वस्थ करने वाली स्कीम फेल घोषित कर दी। 1992 में नई स्कीम पास की जो कि मजदूरों के खिलाफ और अधिक धारदार थी।

– कम्पनी की सम्पत्ति बेचने का सिलसिला जारी। प्लॉट बेचे, मेन्टेनैन्स के बहाने बेचने के लिये प्लान्ट खाली करवाये। प्रोविडेन्ट फण्ड में पैसे जमा नहीं करवाये। तीन-चार महीनों की तनखायें बकाया हुई।

– बैंकों को ब्याज तक फिर अदा नहीं किया। छहों प्लान्टों का उत्पादन निर्धारित का 14 प्रतिशत। बी.आई.एफ.आर. ने 1996 में दूसरी स्वस्थ करने की स्कीम भी फेल घोषित कर दी और मैनेजमेन्ट बदलने के लिये विज्ञापन देने का निर्णय सुनाया।

– बन्द होने की ओर अग्रसर कम्पनी को लूटने में लगी मैनेजमेन्ट विभिन्न क्षेत्रों-स्तरों के अधिकारियों की जेबें भर उन्हें आँखें बन्द करने, मुँह फेरने को राजी करने में बरसों से जुटी थी। ऐसे में 1996 में आदेश देने के बाद सन् 2000 में आ कर बी.आई.एफ.आर. का आँखें खोलना स्वाभाविक है।

हरी झण्डी लूट को

– लूट की रफ्तार तेज। 1996-2000 के बीच फरीदाबाद प्लान्टों में मजदूरों की 27 महीनों की और स्टाफ की 30 महीनों की तनखायें दी ही नहीं। इन चार साल में मजदूरों को जो तनखायें दी भी उनमें डेढ-दो-ढाई हजार रुपये प्रतिमाह काट लिये। गुण्डागर्दी का स्तर फिर बढा कर फैक्ट्री के अन्दर मजदूरों की पिटाई शुरू करवा दी। कुण्डली, औरंगाबाद और जालना प्लान्टों में भी मैनेजमेन्ट का यही ताण्डव।

– जनवरी 2000 में आखिरकार बी.आई.एफ.आर. ने फिर मीटिंग की। मैनेजमेन्ट बदलने और नई स्कीम के लिये विज्ञापन का निर्णय फिर सुनाया तथा मई में अगली मीटिंग तय की। मरे साँप को गले डालने की कोई स्कीम किसी ने पेश नहीं की। इस पर बी.आई.एफ.आर. ने कम्पनी बन्द करने के निश्चय की घोषणा के साथ सुझाव-एतराज के लिये 17 जुलाई की तारीख का विज्ञापन अखबारों में छपवाया।

खुलना पिटारे का

– 17 जुलाई की मीटिंग में कम्पनी के चेयरमैन ने कम्पनी की सम्पत्ति 45 करोड़ रुपये और कर्ज 125-130 करोड़ रुपये बताया। फरीदाबाद प्लान्टों के मजदूरों के ही 60 करोड़

(बाकी पेज चार पर)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद–121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कॉम्पैक्ट टूल्स मजदूर : "कम्पनी का नाम बदलते रहते हैं। 50 से ज्यादा मजदूर हैं पर किसी की भी ई.एस.आई. और फण्ड नहीं है। टूल रूम के सिवा सब ठेकेदारों के वरकर हैं जिन्हें 1400-1500 रुपये महीना देते हैं। तनखा 7 से पहले की बजाय 15 तारीख को देते हैं।"

मेटाफैब इंजिनियरिंग वरकर : "साल-भर तो मजदूर का नाम ही रजिस्टर पर नहीं चढ़ाते। तनखा 1400-1600 रुपये महीना और गालियाँ ऊपर से। दुर्घटना होने पर घर से कोई बुलाने आता है तो 'यहाँ काम नहीं करता' कह कर लौटा देते हैं। पेट तो भरता नहीं और 500 रुपये महीना बैंक में जमा करने के नाम से दबाव डालते हैं।"

विनायक मजदूर : "हैल्परों से मशीनें चलवाते हैं। वेतन 1100 रुपये महीना। हम 300 के करीब हैं पर न ई.एस.आई. है और न फण्ड।"

ई.एस.बी. इन्टरप्राइजेज वरकर : "ई.एस.आई. व फण्ड नहीं हैं और तनखा मात्र 1400 रुपये महीना है।"

एस.पी.एल. मजदूर : "सैक्टर 25 प्लान्ट उस दिन की दिहाड़ी काट लेते हैं।"

प्रिया डाईंग मजदूर : "गर्म काम है। कैजुअल 400 हैं और उन्हें 1800 रुपये महीना देते हैं। कई ठेकेदार भी हैं और उनके वरकरों को तो 1250-1500 रुपये ही देते हैं।"

स्टार वायर वरकर : "1000 में से 90 ही परमानेन्ट हैं। ठेकेदार इतने हैं कि गिनती करना ही मुश्किल है। ठेकेदारों के मजदूरों को 1200-1300-1400 रुपये महीना ही देते हैं। ठेकेदारों के वरकरों और कैजुअलों की न ई.एस.आई. है और न फण्ड। कैजुअलों को मैनेजमेन्ट साप्ताहिक छुट्टी नहीं देती और परमानेन्टों को डी.ए. नहीं देती।"

एस.जी.एल. मजदूर : "साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते। महीने के तीसों दिन काम करने पर 1640 रुपये वेतन बताते थे पर उनमें से प्रोविडेन्ट फण्ड और ई.एस.आई. के नाम से पैसे काट कर हमें 1300 रुपये पकड़ाते थे। जून के पैसों में 30 रुपये और घटा दिये यह कह कर कि 1640 को 1610 कर दिया है। ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। मैनेजमेन्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पुलिस शिकायत करने जाते मजदूरों को ही डराती है। स्टाफ की भी दो महीने की तनखा बकाया हो गई है। ठेकेदारों के वरकरों को 1200-1400 रुपये महीना ही देते हैं और तीन महीनों से वह भी नहीं दिये हैं।"

दुकान कर्मचारी : "साप्ताहिक छुट्टी का कानून है पर सराय ख्वाजा मार्केट की दुकानें हफ्ते में एक दिन भी बन्द नहीं होती और हमें हर रोज खटना पड़ता है।"

सुपर ऑयल सील वरकर : "मार्च माह की तनखा बैलेन्स छोड़ दी है और जून की आज 19 जुलाई तक नहीं दी है।"

बी.एच.डब्लू. कैसल्स मजदूर : "9 जून से ले-ऑफ लगा रही है लेकिन मई का वेतन और ले-ऑफ के पैसे मैनेजमेन्ट ने आज 15 जुलाई तक नहीं दिये हैं।"

बी.के.जी. मैटल वरकर : "आई.एस.ओ. का नम्बर लगा रखा है और हैल्परों को 1200 रुपये महीना तथा आपरेटरों को 1400 देते हैं।

मैनेजमेन्टों की लगाम

हर कार्यस्थल पर हजारों तार होते हैं ; हजारों नट-बोल्ट होते हैं ; नालियाँ-सीवर होते हैं ; कई-कई ऑपरेशन होते हैं ; रात-दिन को लपेटे शिफ्टें होती हैं। इसलिये मैनेजमेन्टों को रोकने-डाटने के लिये मजदूरों के हाथों में कारगर लगाम हैं : ✶ पाँच साल दौड़ने वाली मशीनें छह महीनों में टें बोल दें ; ✶ कच्चा माल-तेल-बिजली उत्पादन के लिये आवश्यक मात्रा से डेढी-दुगनी इस्तेमाल हो ; ✶ ऑपरेशन उल्टे-पल्टे हो कर क्वालिटी को गँगा नहा दें ; ✶ बिजली कभी कड़के, कभी दमके, कभी आँख-मिचौनी करने मक्का-मदीना चली जाये ; ✶ अरजेन्ट मचा रखी हो तब ऐसे ब्रेक डाउन हों कि साहबों को हृदय रोग हो जायें।

बिना किसी प्रकार की झिझक के, शान्त मन से, ठन्डे दिमाग से सोच-विचार कर कदम उठाने चाहियें।

में पी.एफ. और ई.एस.आई. के पैसे काटते हैं पर कार्ड और पर्ची नहीं देते। निकाल देते हैं तब प्रोविडेन्ट फण्ड फार्म नहीं भरते और न ही फण्ड का नम्बर बताते — टाइम आफिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारा कोई रिकार्ड ही नहीं है।"

मैटल एण्ड फॉर्मिंग फैब्रिकेशन वरकर : "हैल्परों को 1400 रुपये महीना ही देते हैं और निकालने के बाद तनखा के लिये डोलाते हैं। न ई.एस.आई. है और न फण्ड।"

इम्पीरियल ऑटो मजदूर : "कैजुअल व ठेकेदारों के वरकरों को साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं देते। महीने के तीसों दिन काम करने पर 1400 रुपये देते हैं।"

आर. के. इंजिनियरिंग वरकर : "महीने के 1100 रुपये देते हैं और वह भी 15 तारीख के बाद। ई.एस.आई. व फण्ड नहीं हैं। चाय तक नहीं देते और पानी पीने जाने पर कहते हैं कि दस मिनट खराब कर दिये। बिजली नहीं होने पर उस दिन की दिहाड़ी काट लेते हैं। छोड़ने पर दस दिन के पैसे काट लेते हैं।"

चाँद इन्डस्ट्रीज़ मजदूर : "मई का वेतन 3 जुलाई को जा कर दिया और जून का आज 15 जुलाई तक नहीं दिया है। माल नहीं होने, बिजली नहीं होने, बारिश होने पर वापस भेज देते हैं और निकाल देते हैं तब प्रोविडेन्ट फण्ड का फार्म भरने से मना कर देते हैं।"

चैम्पियन इंजिनियरिंग वरकर : "250 मजदूरों में से 50 के परमानेन्ट की फीत लगा रखी है पर उन्हें भी देते 1850 रुपये महीना ही हैं। कैजुअल वरकरों में से किसी को भी 1400 रुपये से ज्यादा नहीं देते और किसी को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिया है। ठेकेदारों के मजदूरों को महीने के 1000-1200 रुपये देते हैं।"

फर आटो मजदूर : "जून की तनखा आज 14 जुलाई तक नहीं दी है। हमारे दो साल के प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे मैनेजमेन्ट ने जमा नहीं करवाये हैं।"

कर्मा इंजिनियरिंग मजदूर : "जून की तनखा आज 21 जुलाई तक नहीं दी है। ठेकेदारों के वरकरों को 1500-1600-1700 रुपये महीना देते हैं।"

जगसन पॉल फार्मास्युटिकल वरकर : "कैजुअल मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते और मात्र 64 रुपये दिहाड़ी देते हैं।"

शार्प शॉक्स वरकर : "ज्यादातर मजदूरों को फरवरी से तनखायें नहीं दी हैं। पैसे माँगने पर मारने-पीटने की बात होती है। डी एल एफ पुलिस चौकी में शिकायतों का कोई असर नहीं — ओवर टाइम काम के पैसे डबल की जगह सिंगल रेट से देते हैं।"

आटोपिन मजदूर : "परमानेन्ट वरकरों को मई की तनखा 1-2-3 जुलाई को जा कर दी। कैजुअलों को तो मई की तनखा मैनेजमेन्ट ने आज 15 जुलाई तक भी नहीं दी है।"

हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड वरकर : "हरियाणा सरकार की कंम्पनी है। एक हजार के करीब वरकर हैं जिनमें से 250 डेली वेज हैं — दस साल से लगातार काम कर रहे भी रोजनदारी पर हैं। डेली वेज वरकरों को 57 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जाती है — हरियाणा सरकार अपने द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं देती।"

टी.सी.सी. मजदूर : "पहले वाई एम सी ए का प्लान्ट था। मिट्टी के साँचों में लोहे की ढलाई होती है। तीन ठेकेदार हैं और 1100-1200-1300 रुपये महीना देते हैं। खतरे का काम है — लोहा पानी बना कर इस्तेमाल होता है पर थोड़े से वरकरों को ही ई.एस.आई. कार्ड दिये हैं। ठेकेदार माँ-बहन की गालियाँ बहुत देते हैं और मार-पीट भी करते हैं।"

डाक पता : मज़दूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी. फरीदाबाद—121001

मथ-मथ-मँथन

ग्लोब कैपेसिटर मजदूर : " ऐसी कमाई है कि न हमारा और न बच्चों का पेट भरता है। लेकिन कहाँ जायें ? हर जगह तो यही हाल है। रोना तो हर कोई रोते हैं पर सोचने की बात तो यह है कि ऐसा क्यों होता है।"

मैटल बॉक्स वरकर : " कोई सुनने वाला नहीं है भइया! 16 साल से न तो सरकार ने और न उसके लेबर विभाग ने मजदूरों के लिये कुछ किया है। लीडरों की मत पूछो — अब भी कहते हैं कि कुछ न कुछ होगा जबकि मैटल बॉक्स के आधे मजदूर तो रामपुर जा चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ एक फैक्ट्री में चौकीदारा करने। रोटी के भी लाले पड़ गये हैं। लड़का एक वर्कशॉप में 900 रुपये में काम करता है। बेड़ा गर्क है और कहते हैं कि अपना देश है — इस देश का हम क्या करें।"

नूकेम मशीन टूल्स मजदूर : "4 महीनों की तनखा बकाया होने पर हम ने टूल डाउन की तो मैनेजमेन्ट ने शर्तों पर हस्ताक्षर को फैक्ट्री में प्रवेश के लिये जरूरी करार दिया। कुछ को छोड़ कर हम झाँसे में आ गये और गेट के बाहर हो गये। श्रम विभाग की भूलभुलैया और कानून के लटकों- झटकों को नजदीक से देखा। फँस गये थे इसलिये नुकसान उठा कर फैक्ट्री में लौटे। मैनेजमेन्ट ने दबदबा बढाने के लिये 10 वरकरों को सस्पैन्ड किया। गलत, बल्कि महागलत तो उन 5 मजदूरों ने किया है जिन्होंने पहले कुछ समझदारी दिखाई थी। उन 5 ने सस्पैन्ड वरकरों के खिलाफ मैनेजमेन्ट द्वारा बैठाई जाँच में गवाही दी है। इधर मैनेजमेन्ट ने मई के दो- तीन दिन का और जून का वेतन भी हमें आज 21 जुलाई तक नहीं दिया है।"

एस्कोर्ट्स वरकर : " एग्रीमेन्ट में कार्ड पँच करना है। मैनेजमेन्ट ने क्लास प्लान्ट में 10 जून से कार्ड पँच करने को कहा तो लीडरों द्वारा मना करने पर हम ने पँच करने से इनकार कर दिया। फैक्ट्री में उत्पादन जारी रहा। मैनेजमेन्ट ने 24 जून को कार्ड पँच के लिये अन्तिम तिथि करार दिया। लीडरों के कहे अनुसार हम पँच करने से इनकार करते रहे। मैनेजमेन्ट ने 24 जून को हमें फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करने दिया और यह सिलसिला 27 जून तक चला। फिर लीडर बोले कि कार्ड पँच करो और ऐसा कर हम फैक्ट्री में जाने लगे। मैनेजमेन्ट ने हमारी जून की तनखा में से 1400 जमा 100 रुपये काट लिये हैं और जुलाई के वेतन में से भी 1400 रुपये काटने की बात है। हम अभी चुप हैं पर एक्सपोर्ट की मशीनें बनने वाली हैं और तब हम मैनेजमेन्ट की नाक में दम करके पैसे लौटाने को मजबूर कर देंगे।"

कैनन इण्डिया मजदूर : " सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन तक मैनेजमेन्ट नहीं देती थी। हम ने एक यूनियन का पल्लू पकड़ा। मिनिमम वेज देने की आड़ में मैनेजमेन्ट ने पहले तो 50 स्थाई श्रमिकों को बाहर निकाल दिया और कुछ दिन बीतने के बाद 46 अन्य श्रमिकों को भी निकाल दिया। मजदूरों के हित में कोई कुछ नहीं करता और न ही कहीं न्याय है। मैनेजमेन्ट कहती है : ' तुम लोग कहाँ जाओगे ? तुम जहाँ जाओगे वहाँ हमारा पैसा काम करेगा। हम ने सब को खरीद रखा है।' तीन साल से लगातार काम कर रहे श्रमिकों को निकालना शुरू कर रखा है। सरकार का यह हाल है कि 7 जुलाई को श्रम विभाग के एक अधिकारी ने एक वरकर को फैक्ट्री में थप्पड़ मारा और फिर उसे थाने में बन्द करवा दिया।"

सीधे-टेढे जाल

स्काईटोन केबल्स मजदूर : " लीडरों ने एग्रीमेन्ट के लिये माँग- पत्र दिया, मैनेजमेन्ट ने अनुशासन की बातें की। आज, 22 जुलाई को मैनेजमेन्ट ने शर्तों पर हस्ताक्षर करने को फैक्ट्री में प्रवेश की शर्त बनाया। लीडरों ने कहा कि दस्तखत नहीं करना। इस प्रकार हम बाहर कर दिये गये हैं। अब क्या करें ? मेरे हाथ में, किसी मजदूर के हाथ में अब मामला नहीं रहा। बात लीडरों के हाथ में हो गई है और यही बीमारी है। बरसों से काम कर रहे कैजुअलों को निकालना तो शुरू किया ही हुआ था, मामला और गड़बड़ लगता है — हम फँसा दिये हैं।"

टालब्रोस वरकर : " कोई बड़ा लफड़ा है। मैनेजमेन्ट ने जानबूझ कर पँगा लिया। एक सुपरवाइजर ने एक मजदूर को छेड़ा और फिर मैनेजमेन्ट ने उस मजदूर को सस्पैण्ड कर दिया। लीडरों ने इस पर स्लो डाउन करवाया। 22 जुलाई को स्लो डाउन शुरू होते ही मैनेजमेन्ट ने 450 कैजुअल वरकरों को गेट बाहर कर दिया। फिर मैनेजमेन्ट ने 4 लीडरों को सस्पैण्ड किया। इस प्रकार बात बढा कर शनिवार, 29 जुलाई को मैनेजमेन्ट ने प्लॉट 75 के वरकरों के लिये शर्तों पर हस्ताक्षर करने को फैक्ट्री में प्रवेश की शर्त बनाया और प्लॉट 74 के वरकरों को वैसे ही रोक दिया। लगता है कि कटलर हैमर मजदूरों द्वारा मैनेजमेन्टों के शर्तों वाले जाल को काट देने के दृष्टिगत टालब्रोस मैनेजमेन्ट ने टेढा जाल बिछाया। लीडरों ने कहा कि शर्तों पर हस्ताक्षर मत करो। इस प्रकार दोनों प्लान्टों के हम 200 परमानेन्ट मजदूर भी फैक्ट्री के बाहर कर दिये गये हैं। गेट बाहर कर नूकेम मशीन टूल्स वरकरों की ही तरह हम फँसा दिये हैं।"

बीज बबूल के

हैदराबाद इन्डस्ट्रीज मजदूर : " यह वी.आर.एस. नहीं बल्कि सी.आर.एस. होती हैं पर सरकार ऐसे दिखावा कर रही है जैसे उसे पता ही नहीं हो। वी.आर.एस. में जो नौकरी छोड़ते हैं उनकी जगह नई भर्ती नहीं करते — जो नौकरी में बचे रहते हैं उन्हें ही अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। वी.आर.एस. में जॉब खत्म करते हैं इसलिये इसकी असली चोट हमारे बच्चों पर पड़ती है — कैजुअल और ठेकेदारों के वरकर बनना ही उनका भविष्य रह जाता है।"

आयशर ट्रैक्टर वरकर : "4 जुलाई को वी.आर.एस. का नोटिस लगा मजदूरों को अकेले- अकेले बुला कर साहबों ने नौकरी छोड़ने को कहा। बात फैलने पर सीनियर मैनेजरों ने मीटिंग कर किसी वरकर से जबरदस्ती नहीं करने वाले रस्मी भाषण दिये। 60 स्टाफ वालों को और 395 में से 120 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है। टूल रूम खत्म कर दिया है और मशीन शॉप का काम भी फैक्ट्री से बाहर करवायेंगे। इक्के- दुक्के जो वी.आर.एस. में फायदा देख कर नौकरी छोड़ते हैं वो यह भूल जाते हैं कि वी.आर.एस. जॉब खत्म करने का एक जरिया है। रिटायर होने के निकट वरकरों को दो पैसे फालतू दे कर वी.आर.एस. के तहत नौकरी छुड़वा कम्पनियाँ हमारे बच्चों का भारी नुकसान करती हैं।"

एस्कोर्ट्स मजदूर : "साल पीछे 107 दिन के पैसों वाली वी.आर.एस. के झाँसे में भी वरकर नहीं आये। तब मैनेजमेन्ट ने स्टोर, प्लानिंग, इन्सपैक्शन, टूल रूम, सैनिटेशन से लोगों को ट्रान्सफर कर उत्पादन में लगाया। इन ट्रान्सफरों पर किसी ने कोई एतराज नहीं किया, कोई हँगामा नहीं किया। इससे मैनेजमेन्ट और परेशान हो गई क्योंकि बड़े पैमाने पर छँटनी की उसकी बात बन नहीं रही थी। इधर मैनेजमेन्ट ने एक और पाँसा फेंका है। सैकेन्ड प्लान्ट (राजदूत- यामाहा) में मैनेजमेन्ट ने धमाकेदार वी.आर.एस. लगाई है। बाकि बची सर्विस के लिये आयु के 52 वर्ष पूरे कर चुके वरकरों को नौकरी छोड़ने पर 80- 85 प्रतिशत वेतन का चुग्गा डाला है। एक लड़की के लिये तीस हजार, दो के लिये साठ हजार ऊपर से! दरअसल जॉब खत्म करने के हमें दो रुपये एक्स्ट्रा दे कर हमारे बच्चों को एक हजार का नुकसान करने की यह नई स्कीम है। एक पीढी दूसरी पीढी की नहीं सोचेगी तो दोनों का बेड़ा गर्क होगा।"

भूख लगी तो जहर खाया : इन्द्रराज को जब रोटी के लाले पड़ गये तो उसे भूख मिटाने के लिये जहर खाना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार गाँव मडनाका निवासी इन्द्रराज लगभग दो साल पहले झालानी टूल्स से सेवानिवृत हो गया था। जब से वह सेवानिवृत हुआ तभी से वह अपने कार्यकाल का हिसाब- किताब लेने के लिये कारखाने के चक्कर लगा रहा था। उसे रोजाना आज आना, कल आना कह कर टाल दिया जाता रहा जिससे दुखी हो कर इन्द्रराज पुत्र अतर सिंह ने जहर खा कर मौत को गले लगा अपनी जिन्दगी से छुटकारा पा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिवारजनों को सौंप दिया है। (पंजाब केसरी, 27 जलाई 2000)

वाह-वाह !

कम्पाउन्डर : "एक आदमी आया और छाती में दर्द है कहते हुये सीधा डॉक्टर साहब के पास चला गया। पर्ची बनवा कर आओ कहने पर वह बोला कि उसके पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब ने बिना पर्ची के उसे देखने से मना कर दिया। दो घण्टे बाद उस आदमी ने 40 रुपये दे कर पर्ची बनवाई। डॉक्टर साहब हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और छाती में दिल के ऊपर चोट देख कर एक्स-रे, ई.सी.जी. आदि करवाने को कहा। इस पर वह आदमी फिर बोला कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसकी बात पर ध्यान दिये बिना डॉक्टर साहब ने पूछा कि चोट लगी कैसे। वह आदमी बोला कि एक खाग्गड़-साँड दौड़ते हुये एक रुकावट को देख कूदा तो लोहे की छड़ पेट में घुस गई। दर्द से तड़फड़ाते खाग्गड़ को उसने चार लोगों के साथ मिल कर काबू में किया और उस दौरान छाती में चोट लग गई। डॉक्टर साहब ने पूछा कि खाग्गड़ के पेट से लोहे की छड़ निकाल दी कि नहीं तो वह आदमी बोला कि हाँ, निकाल दी। 'चलो टैस्ट करवाओ' कहने पर वह आदमी फिर बोला कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इस पर पर्ची के 40 रुपये लौटाते हुये डॉक्टर साहब बोले कि टैस्टों के पैसे उसे नहीं देने होंगे और दवाई भी मुफ्त मिलेगी।"

विकास-प्रगति की दलदल

हैदराबाद इन्डस्ट्रीज मजदूर : "मल्टीट्रेड की नई बीमारी तेजी से फैल रही है। किसी चीज की कोई हद नहीं रही। पचास वर्ष आयु के एक ट्रेड में दक्ष कारीगरों को मैनेजमेन्ट अन्य ट्रेड सीखने के लिये आई.टी.आई. में लड़कों के साथ सीखने भेजती है।"

साधु उद्योग वरकर : "यह कह कर कि आर्डर नहीं हैं, मैनेजमेन्ट ने गियर डिविजन के 60 मजदूर नौकरी से निकाल दिये हैं।"

फ्रिक इण्डिया मजदूर : "हालात को देख कर अपनी दाल-रोटी चलते देख कभी-कभी सन्तुष्ट हो जाता हूँ पर बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि इनका क्या होगा तो मन में आता है कि चलती ट्रेन के नीचे आ कर कट जाऊँ।"

जी.बी.एम. वरकर : "आर्डर मिले हैं और हमारी आफत आ गई है। रोज 16 घण्टे काम करना कम्पलसरी किया हुआ है। ओवर टाइम के पैसे भी डबल नहीं सिंगल रेट से देते हैं।"

टेकमसेह मजदूर : "नौकरी छोड़ने को मजबूर करने के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। काम नहीं होता तब भी बैठने नहीं देते। खड़े-खड़े हमारे पैर सूज जाते हैं।"

गवर्नमेन्ट प्रेस वरकर : "बड़े जॉब तो मैनेजमेन्ट बाहर करवा ही रही थी, इधर विशेषज्ञों को चीर-फाड़-अध्ययन के लिये लाया गया है। विशेषज्ञ यह पता करेंगे कि कितने मजदूर निकाले जा सकते हैं और कितना वर्क लोड बढाया जा सकता है। छँटनी की तलवार हमारे सिर पर भी मँडराने लगी है।"

जे. एम. ए. मजदूर : "पहले तो बड़े-बड़े अफसर आये और प्रोडक्शन-प्रोडक्शन की बातें की लेकिन अब फिर तरीका सख्ती का है। पहले उत्पादन बढवाओ और फिर सख्ती करो अन्य फैक्ट्रियों में भी छँटनी के लक्षण रहे हैं। टूल रूम के सब 13 मजदूरों को निकाल कर अब वी. आर.एस. की चर्चा आरम्भ की है।"

शाही एक्सपोर्ट्स मजदूर : "कम्पनी में पेशाब करने या पानी पीने के लिये कूपन लेना जरूरी है। एक कूपन पर एक ही मजदूर जा सकती-सकता है और बड़ी-बड़ी डिपार्टमेन्ट में दो ही कूपन हैं। सब वरकरों को ड्युटी के दौरान एक चाय देते थे। उसे बन्द कर महीने के 30 रुपये देने लगे जबकि चाय का एक कप 2 रुपये से कम में नहीं मिलता। टुच्चेपन में एक कदम और आगे बढ मैनेजमेन्ट चाय के यह 30 रुपये भी पुराने वरकरों को ही देती है — नये वरकरों को न तो चाय है और न पैसे। ओवर टाइम काम जबरदस्ती करवाते हैं लेकिन पेमेन्ट डबल की बजाय सिंगल रेट से ही देते हैं। कभी-कभी तो लगातार 24 घण्टे काम करवाते हैं।"

एक चपरासी : "ओखला में डी — 53 फेज—1 में मैं 11 साल से चपरासी था। सोचता था कि रिटायर हूँगा तब मोटी रकम मिलेगी और गाँव में कोई धन्धा करके बाकी जिन्दगी चैन से गुजारूँगा। मेरे सपने पिछले महीने उस समय टूट गये जब मैनेजमेन्ट ने मुझे मासिक वेतन के साथ निकाल दिया। मैंने प्रोविडेन्ट फण्ड और सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसों की बात की तो यह कह कर टाल दिया कि तुम्हारा कोई रिकार्ड नहीं है। मैनेजमेन्ट ने कम्पनी का नाम और काम दोनों बदले हैं — मैं लगा तब एक्सपोर्ट का था और अब मेरा हिसाब हुआ है तब इन्टरनेट का काम है।"

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये :

★ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते।

★ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये।

★ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये-पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार ही छाप पाते हैं और 5000 प्रतियाँ ही फ्री बाँट पाते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें।

निराशा हैं आशा की किरण....

(पेज एक का शेष)

रुपये कम्पनी में फँसे होने का तथ्य सामने लाये जाने पर कम्पनी की देनदारी 200 करोड़ रुपये से ऊपर जाते देख कम्पनी चेयरमैन हड़बड़ाया। लेकिन फिर भी मैनेजमेन्ट ने 23 जून को सौंपी स्वस्थ करने की नवीनतम स्कीम के लिए खूब कसरत की। स्कीम में कम्पनी चलाने के लिए कम्पनी की 15 करोड़ रुपये की और सम्पत्ति बेचने की बात प्रमुख थी। मैनेजमेन्ट 2 करोड़ रुपये और अमरीका से कोई 25 करोड़ रुपये लगायेंगे का लेप भी संग था। लीडर तो उसके थे ही, एक बैंक अधिकारी को फिर मैनेजमेन्ट ने अपनी बोली बोलने को तैयार किया था।

— लेकिन कुछ मजदूरों ने अपने पैसों के लिये बी.आई.एफ.आर. कार्रवाई में हस्तक्षेप किया। फिर, जगह-जगह जेबें भरी जाने के बावजूद पानी सिर से बहुत ऊपर चला गया था। इधर स्वयं बी.आई.एफ.आर. के सिर पर तलवार मंडरा रही है। ऐसे में बी.आई.एफ.आर. को कम्पनी बन्द करने, वाइन्ड अप करने का आदेश देना पड़ा।

लाइलाज लार

— झालानी टूल्स के हर मजदूर की कम्पनी पर तीन लाख रुपये की लेनदारी है। लेकिन कम्पनी की सम्पत्ति 45 करोड़ रुपये और देनदारी 200-250 करोड़ रुपये के दृष्टिगत डेढ लाख रुपये तो हर मजदूर के डुबो दिये गये हैं। और अब भी कट/लूट के चक्कर में मैनेजमेन्ट कम्पनी की बची-खुची सम्पत्ति बेचने की फिराक में है। कम्पनी बन्द करने के आदेश के खिलाफ इसीलिये मैनेजमेन्ट अपील कर रही है।

— "अमरीका से कोई कम्पनी पैसे लगायेगी, डायरेक्टर का साला पैसे लगायेगा, कम्पनी की सम्पत्ति बेचने से 15 करोड़ रुपये आयेंगे। इन पैसों में से कुछ पैसे बैंकों को दे कर कम्पनी चलेगी। कम्पनी चलेगी तो पैसे मिलेंगे इसलिये कम्पनी चलनी चाहिये। किसी बन्द कम्पनी के मजदूरों को पैसे नहीं मिले हैं।" — यह तर्कबाण लूट में टुकड़ों के लिये मैनेजमेन्ट का लीडरी विभाग गुण्डागर्दी के संग-संग इस्तेमाल कर रहा है। कम्पनी चलती रहे-नौकरी बनी रहे का यह झाँसा कम्पनी की बची हुई सम्पत्ति बेच खाने और मजदूरों के बाकी पैसे भी डुबोने के लिये है।

दरारें कालकोठरी में

वेतन नहीं और गुण्डागर्दी को झेलते, सरकारी तन्त्र-मैनेजमेन्ट तन्त्र की हकीकत को देखते, आस्था रूपी अनेकों भ्रमों को त्यागते झालानी टूल्स मजदूर स्वयं कदम उठाने की राहों पर अग्रसर हुये हैं। मजदूरों के खुद के चन्द कदमों ने ही मैनेजमेन्ट के जाल में बड़े-बड़े छेद कर दिये हैं। कम्पनी की सम्पत्ति की नीलामी के जरिये मजदूरों द्वारा अपने कुछ पैसे हासिल करना तो इसका एक परिणाम मात्र होगा। (जारी)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।